भविष्य से भयाक्रांत शासक वर्ग का नया हथियार – 'पोटो'

कविता

पोटो का दैत्य नये रंग-रोगन के साथ हमारे सामने है! मामूली संशोधनों के बाद आतंकवाद निरोधक अध्यादेश "आतंकवाद" का सफाया करने आ चुका है। जिस तरह से आपातकाल के काले अंधेरे दौर में "आन्तरिक सुरक्षा" पर खतरे के नाम पर कुख्यात 'मीसा' लागू हुआ, बाद में 'रासुका' आया, आंतकवाद से निपटने के लिए टाडा बनाया गया, आज ऐसे ही जनतंत्र निषेधी काले कानूनों का चरम है – 'पोटो'।

लुटेरे हुक्ममरानों की जंगी मुहिम, जो कि आंतकवाद को कुचलने के नाम पर पूरी दुनिया के जनता के खिलाफ चलाई जा रही है, में हिन्दुस्तान का शासक वर्ग भी बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी कर रहा है। दरअसल, जनविरोधी आर्थिक नीतियों के कारण समाज में हो रही तबाही-बर्बादी के कारण जनअसंतोष का लावा सतह के नीचे खदबदा रहा है। पूरा समाज ज्वालामुखी के मुहाने पर खड़ा है। सत्ताधारी वर्ग इस खतरे को भांप रहा है। साम्राज्वाद के सामने घुटने टेक चुका हमारे देश का जन विमुख शासक वर्ग भविष्य के इसी खतरे से निपटने के लिए दमन के हरबे हथियारों से खुद को लैस कर लेना चाहता है। पोटो एक ऐसा ही हथियार है।

पोटो ने जालिम पुलिस मशीनरी को किसी भी नागरिक की गलत मंशा का पता लगा लेने का वरदान दे दिया है(भले ही उस नागरिक को अपनी गलत मंशा स्वयं न पता हो)। पोटो के प्रावधानों के तहत ऐसे किसी भी व्यक्ति को अपराधी घोषित किया जा सकता है जिसके बारे में पुलिस को यह पता लग जाये कि उसकी मंशा भारत की एकता, अखण्डता, सुरक्षा या सम्पभुता को खतरा पहुंचाना अथवा जनता के किसी भी तबके के भीतर आंतक पैदा करना है।

यह अनुमान लगाना कठिन नहीं है कि सरकार के किसी भी जनविरोधी कदम के खिलाफ पर्चा बांटना, सभा करना, जुलूस-रैली निकालना, लेख लिखना, गीत गाना, या किसी खास समय पर खास जगह पर मौजूद रहना ही पोटो के दायरे में लाये जाने के लिए काफी होगा। पोटो जारी होने के पहले ही अफगानिस्तान पर अमेरिकी हमले के विरोध में दिल्ली में पर्चा बांट रहे छह छात्रों को देश द्रोह के आरोप में गिरफ्तार करके सरकार ने साफ तौर पर सरकार ने अपनी मंशा का सुराग दे दिया था।

पोटो लागू करने के पीछे आतंकवाद तो बहाना है, असली निशाना तो जनता है। आतंकवाद न 'टाडा' से खत्म हुआ था और न 'पोटो' से होगा। ओसामा बिन लादेन और भिण्डरावाले को पैदा करने वाली सत्ताओं की मंशा को समझना बहुत जरूरी है। सरकार का यह कहना कि पोटो के तहत निरपराध लोगों, अल्पसंख्यकों, पत्रकारों, वकीलों, शिक्षको, कलाकारों, जनतांत्रिक अधिकार संगठनों के कार्यकर्त्ताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, मात्र एक छलावा है। संशोधित पोटो के प्रारूप से भी यह साफ हो जाता है। यह एक जलता हुआ सच है कि पूर्ववर्ती कानून टाडा के तहत देश भर में जेलों में ठूंसे गये 76,000 लोगों में से महज एक प्रतिशत ही लोगों को सजा योग्य पाया गया। हजारों बेगुनाह जेलों में सड़ते रहे। टाडा खत्म होने के बाद आज भी करीब पन्द्रह हजार लोग सलाखों के पीछे कैद हैं।

जिन लोगों को सलाखों के पीछे होना चाहिए था, वे सत्तासुख भोग रहे हैं। जो देश को बेच रहे है, विदेशी लुटेरों के साथ

दिशा छात्र संगठन और अन्य संगठनों के कार्यकर्ता दिल्ली में पोटो के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए

मिलकर जनता को लूट रहे हैं, बड़े माफिया-तस्कर-घोटालेबाज सत्ता के गलियारों में घूम रहे हैं। कफन-खसोट मुर्दाखोर साम्प्रदायिक उन्माद पैदा करने वाले, फासिस्ट गुण्डा गिरोह, आर्थिक अपराधी, काले धन की समान्तर सत्ता चलाने वाले, मौत के सौदागर क्या इन पर भी कोई पोटो लागू होगा। पोटो दरअसल इनके खिलाफ उठने वाली हर अवाज को कुचलने के लिए बना है।

अन्याय और लूट पर टिका निजाम जब तक कायम है, जब तक सरकारी आतंकवाद कहर ढा रहा है, आतंकवाद की नयी-नयी किस्में पैदा होती रहेगी, क्रांतिकारी शक्तियां जब तक कमजोर रहेगी, तब तक हताश-निराश-परेशान नौजवानों के एक हिस्से को आतंकवाद अपनी ओर खीचता रहेगा। आतंकवाद किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, उसकी नियति अंधी गली में जाकर दम तोड़ देना है। आतंकवादी गिरोह नहीं जनता के इंकलाबी जनसंगठन जनता को मुक्ति की राह दिखाते हैं। इसीलिए लुटेरी जालिम सत्ताओं के लिए आतंकवाद नहीं, बल्कि जनपक्षधर संघर्षशील ताकतें चुनैती होती हैं। आतंकवाद तो एक अच्छा बहाना है, जिसकी आड़ में जनपक्षधर, इंसाफपसंद लोगों, संगठनों पर निशाना साधा जाता है। पोटो के प्रावधानों को देखकर इस बात को अच्छी तरह समझा जा सकता है। पोटो के पीछे इसी 'मंशा' के कारण पोटो के विरोध में जनता के बीच से अवाजें उठीं।

पोटो पर संसद में पक्ष-विपक्ष की नूराकुश्ती मात्र एक दिखावा है। पोटो के खिलाफ विपक्ष की चीख-पुकार महज धोखे की टट्टी है। आज विपक्ष में बैठी कांग्रेस जो आपातकाल के हत्यारे दिनों से लेकर टाडा तक का सफर तय करके सयानी बनी हुई है, का विरोध नकली विरोध है। दिल्ली में कांग्रेस की ही सरकार है जिसने 'मोक्का' लागू किया है। मोक्का(महाराष्ट्र कन्ट्रोल आफ आर्गनाइज क्राइम एक्ट) पहले से ही महाराष्ट्र में लागू किया जा चुका है। नकली वामपंथियों के नपुंसक विरोध और उनकी बेशर्मी का क्या कहा जाए, ये केन्द्र में 'जनपक्षधर' हो जाते है और अपने राज्य में जाते ही गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं। पश्चिम बंगाल में 'पोका' कानून लाने के लिए एक असफल प्रयास किया भी जा चुका है। जिस चुनावबाज पार्टी को देखिये, वह इस दोगलेपन में उस्ताद है। और आज भाजपा की अगुआई वाली गठबंधन सरकार इन सबकी सिरमौर बनी हुई है।

अपने को "राष्ट्रवादी" "स्वदेशी" कहते नहीं अघाते "राष्ट्रभक्त" अमेरिका की चरण वंदना में इतने मशगूल हैं और वे भूल रहे हैं कि हर देश का अपना एक स्वाभिमान होता है। देश किसी गिरोह की बपौती नहीं है, न वह कोई चरागाह है जहां भेड़ों का रेवड़ रहता है। हिन्दुस्तान की तस्वीर और तकदीर का फैसला करने वाली सरकारों को याद रखना चाहिए कि अमेरिका और उसके लगुओं-भगुओं के साथ उनकी सांठ-गांठ को इस देश को प्यार करने वाली मेहनतकश जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। भले ही आज दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी देश शांति का मसीहा बना हुआ हो और उसका भारत में राजदूत यह बयान दे रहा हो कि अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का नया दौर तय किया है। अमेरिका ने पहले चरण में अलकायदा और अफगानिस्तान पर ध्यान दिया और अब भारत में आतंकवाद की समस्या को देखेगा।

अमेरिकी राजदूत राबर्ट ब्लैकविल के इस ताजा बयान पर यही कहा जा सकता है कि साम्राज्यवादियों की तमाम देशों के निजी मामलों में हस्तक्षेप के पीछे की कुत्सित मंशाओं को जनता ने पहले भी धूल चटाई है। और आज भी लाख पोटो होने के बावजूद, जनता देशी विदेशी लुटेरों के नापाक गठबंधन की तीन तिकड़मों, साजिशों को धूल चटायेगी ही, चाहे इसमें कुछ वक्त लगे। इसका अपवाद आज भी नहीं होगा।

शासक वर्ग भय के मनोविज्ञान और दमन के हथियारों के सहारे बहुत दिनों तक अपना वजूद कायम नहीं रख सकता। दरअसल, यह शासक वर्गो की मजबूरी के बजाय उसकी कमजोरी का ही सूचक है। आतंकवाद से निपटने के नाम पर शासक वर्गो के आतंकवाद और भय के मनोज्ञिान को चीरने की जिम्मेदारी यूं तो समाज के सभी इन्साफपसंद, जनतंत्रप्रिय लोगों की है, पर नौजवानों की यह जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाने के लिए सबसे आगे आना चाहिए।

●

जिस धरती पर हर अगले मिनट एक बच्चा भूख या बीमारी से मरता हो, वहां पर शासक वर्ग की दृष्टि से चीजों को समझने की आदत डाली जाती है। लोगों की इस दशा को एक स्वाभाविक दशा समझने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। लोग व्यवस्था को देशभक्ति से जोड़ लेते हैं और इस तरह से व्यवस्था का विरोधी एक देशद्रोही अथवा विदेशी एजेण्ट बन जाता है। जंगल के कानूनों को पवित्र रूप दे दिया जाता है ताकि पराजित लोग अपनी हालत को अपनी नियति समझ बैठें।

– एदुआर्दो खालीआनो (अर्जेण्टीना के लेखक)

दायित्वबोध

उन बुद्धिजीवियों की पत्रिका जिन्होंने जनता का पक्ष चुना है

सम्पादकीय कार्यालय :
81, समाचार अपार्टमेण्ट
मयूर विहार फेज-एक
दिल्ली-110091
फोन : 011-2711136
email :
dayitvabodh@rediffmail.com

एक प्रति : 15 रुपए
वार्षिक : 60 रुपए
(डाक व्यय सहित 72 रुपये)
आजीवन : 1000 रुपये